



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]  
No. 103]नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2011/ज्येष्ठ 2, 1933  
NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2011/JYAISTA 2, 1933

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क प्राधिकारी विभाग)

जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2011

विषय : चीन जन.गण. और थाइलैंड के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (फोर्ड मीडिया बॉल्स को छोड़कर) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत।

सं. 14/34/2010-डीजीएडी.—यतः मै. एआईए इंजीनियरिंग लि. तथा मै. वेलकास्ट स्टील्स लि. (जिन्हें एतदपश्चात् आवेदक कहा जाएगा) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें उन्होंने चीन जन.गण. और थाइलैंड के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (फोर्ड मीडिया बॉल्स को छोड़कर) (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया है और संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जाँच शुरू किए जाने का अनुरोध किया है।

## विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद फोर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (“कार्स्टिंग बॉल्स” के नाम से भी ज्ञात) है (जिसे एतदपश्चात् “संबद्ध वस्तु” कहा गया है)। “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (संक्षेप में “जीएम बॉल्स”) का उत्पादन विभिन्न अनुप्रयोजनों में उपयोग हेतु विभिन्न मापों, आकारों तथा संघटनों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों की अलग-अलग अपेक्षाओं के अनुसार यह विभिन्न कठोरताओं में उपलब्ध होता है।

3. विचाराधीन उत्पाद का व्यापक उपयोग सीमेंट बिल्ड सामग्री, धातु खान, कोयला गारा, ताप विद्युत संयंत्र, रसायन इंजीनियरी, सेरेमिक उद्योग, डोप उद्योग, पाउडर तैयार करने के लिए पेपरमेकिंग तथा चुम्बकीय सामग्री आदि जैसे प्रकाश उद्योग में होता है। संबद्ध वस्तु सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 73 के सीमा-शुल्क उप-शीर्ष 7325 9100 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

## घरेलू समान वस्तु

4. आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं एवं संबद्ध देशों द्वारा नियातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात विशेष अंतर नहीं है। भरतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक एवं सामाजिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्रयोक्ताओं द्वारा दोनों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है।

5. इसलिए वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

## घरेलू उद्योग एवं "स्थिति"

6. घरेलू उद्योग की ओर से यह आवेदन मै0 एआईए इंजीनियरिंग लि�0 और मै0 वेलकास्ट स्टील्स लि�0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मै0 एआईए इंजीनियरिंग लि�0, मै0 वेलकास्ट स्टील्स लि�0 की सहायक कम्पनी है। आवेदन के अनुसार भारत में संबद्ध उत्पाद के दो और ज्ञात उत्पादक हैं।

7. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों का 90% से अधिक हिस्सा है और इसलिए घरेलू उत्पादन में आवेदकों का प्रमुख हिस्सा है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों का "प्रमुख हिस्सा" है। अतः आवेदक "स्थिति" संबंधी अपेक्षा को पूरा करते हैं और पाठनरोधी नियमों के अनुसार "घरेलू उद्योग" हैं।

## शामिल देश

8. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जन.गण. और थाइलैंड हैं (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है)।

## सामान्य मूल्य

### चीन जन.गण

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचनागत मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि उनके पास संगत सूचना उपलब्ध नहीं है और विधि में किए गए निर्धारण के अनुसार सामान्य मूल्य "बाजार अर्थव्यवस्था वाले ऐसे तीसरे देश में खपत हेतु अभिप्रेत समान वस्तु के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत" है। उन्होंने दावा किया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उत्पादक से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यह भी दावा किया गया है कि अन्य देशों के लिए

बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों की कीमत पर निम्नलिखित कारणों से निर्भर नहीं रहा जा सकता है, (क) संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है; (ख) इस प्रकार अंगीकार की गई कीमत व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में कीमत होनी चाहिए; (ग) ऐसी सूचना के लिए ऐसे तीसरे देश का सहयोग अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, भारत हेतु ऐसे तीसरे देश की कीमतों को अंगीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कीमतें संबद्ध देशों की कीमतों से प्रभावित हो सकती हैं और संबंधित उत्पाद में कई प्रकार के ग्रेड शामिल हैं जिनमें सहयोगी लागत और कीमत के रूप में अत्यधिक अंतर होता है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए भास्त उपयुक्त सहोदर देश है।

10. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 में दी गई अन्य पद्धतियों के संबंध में पर्याप्त सूचना के अभाव में 'किसी अन्य तर्कसंगत आधार' पद्धति को अंगीकार करके सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ सहित भारत में संबंधित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

### थाइलैंड

11. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके द्वारा थाइलैंड के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमतों के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे और प्रकाशित सामग्री से भी कीमतों के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, थाइलैंड के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री की वास्तविक सौदा कीमतों और उन वास्तविक सौदा कीमतों जिन पर थाइलैंड से दूसरे देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, के प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त करने के सभी उचित प्रयासों के बावजूद वे इस संबंध में पर्याप्त एवं विशुद्ध साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। अतः उन्होंने थाइलैंड में जीएम बॉल्स की अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

12. तथापि, प्राधिकारी ने थाइलैंड से तीसरे देशों को जीएम बॉल्स के निर्यात के संबंध में ऑकड़े एकत्र किए थे। यद्यपि ऑकड़े ग्रेड-वार आधार पर उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी इस जाँच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ वैकल्पिक आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में इन ऑकड़ों पर विचार किया गया है।

### निर्यात कीमत

13. आवेदकों ने निर्यात कीमत का निर्धारण आईबीआईएस, मुम्बई से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर किया है। कारखाना द्वारा निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाष्टा, समुद्री बीमा, कमीशन, निर्यातक देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन व्यय तथा बैंक प्रभार आदि के लिए निर्यात कीमत में समायोजन किया गया है।

### पाटन मार्जिन

14. आवेदकों ने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है

कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करता है ।

### 'क्षति' एवं कारणात्मक संबंध

15. आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति का दावा किया है । यह दावा किया गया है कि आयातों में सापेक्ष रूप से और भारत में खपत की तुलना में वृद्धि हुई है और आयातों के कारण घरेलू कीमतों में अत्यधिक कटौती हुई है । इसके अतिरिक्त आवेदक ने बाजार हिस्से, बिक्री, नकद लाभ, नियोजित पूँजी पर आय और माल सूची के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट का दावा किया है ।

16. नियमावली के अर्थ के भीतर पाटनरोधी जांच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को 'क्षति' हुई है ।

### पाटनरोधी जांच की शुरुआत

17. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का मत है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को 'क्षति' और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराते हैं । तदनुसार प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा, प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि जो अधिरोपित किए जाने पर घरेलू उद्योग की क्षति की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' की जांच की शुरुआत करते हैं ।

### जांच की अवधि

18. आवेदकों द्वारा अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2010 तक की अवधि को जाँच अवधि मानने का प्रस्ताव किया गया है । केवल जाँच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ इस अवधि को जाँच की अवधि मानते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जनवरी, 2010 से दिसम्बर 2010 तक की अवधि को जांच की अवधि माना है । तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2007-मार्च, 2008, अप्रैल 2008-मार्च, 2009, अप्रैल 2009-मार्च 2010 तथा जांच की अवधि (पी ओ आई) अर्थात जनवरी 2010 से दिसम्बर 2010 तक की अवधि शामिल होगी । वास्तविक क्षति के खतरे के लिए पी ओ आई के बाद की अवधि के आंकड़ों की भी जांच की जाएगी ।

सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातक, भारत में स्थित उनके द्वृतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में मौजूद संबद्ध ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित ढंग एवं पद्धति से संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**कमरा सं० 243**  
**उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107**

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित ढंग एवं पद्धति से इस जांच से संगत निवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

समय सीमा

21. इस समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई हेतु अनुरोध लिखित रूप में प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराना

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय के रूप में चिन्हित, (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या इत्यादि सहित) तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या इत्यादि सहित)। प्रस्तुत की गई प्रत्येक सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होना आवश्यक है।

23. किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति देने का अधिकार होगा । गोपनीय तथा अगोपनीय रूपांतर की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

24. जिस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया हो, उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ इस बात का ठोस कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना को क्यों प्रकट नहीं किया जा सकता तथा/अथवा ऐसी सूचना का सारांश करना क्यों संभव नहीं है ।

25. अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए जिसमें सूचना की गोपनीयता के दावे के आधार पर गोपनीय सूचना को सूचीबद्ध किया जाए/अथवा वह स्थान रिक्त रखा जाए । अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का अर्थ समुचित रूप से स्पष्ट हो सके । तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह निवेदन कर सकता है कि प्रस्तुत की गई सूचना का सारांश करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांश संभव न होने का कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

26. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता हेतु अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है । यदि प्राधिकारी इस बात रो संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा सामान्य या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं ।

27. प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी सूचना को उसके साथ उसके एक सार्वर्थित अगोपनीय रूपांतर अथवा गोपनीयता का दावा करते हुए ठोस कारण दर्शाते हुए विवरण के बिना, अस्वीकार किया जा सकता है । प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने तथा गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने के पश्चात, ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उस सूचना को किसी पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे ।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षों के अगोपनीय सारांश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

### 'उपलब्ध तथ्यों' का उपयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

## INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2011

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of 'Grinding Media Balls' (excluding Forged Grinding Media Balls) originating in or exported from Thailand and China PR**

**No. 14/34/2010-DGAD.**—Whereas M/s AIA Engineering Ltd and M/s Welcast Steels Limited, (hereinafter referred to as the Applicants ) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the AD Rules), alleging dumping of 'Grinding Media Balls' (excluding Forged Grinding Media Balls) (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Thailand and China PR (hereinafter also referred to as the subject countries) and has requested for initiation of anti- dumping investigation and levy of anti dumping measures.

**Product under consideration**

2. The product under consideration is 'Grinding Media Balls' (also known as 'Casting Balls') excluding Forged Grinding Media Balls (hereinafter also referred to as the 'Subject goods'). 'Grinding Media Balls' (in short, 'GM Balls') are produced in different sizes, shapes and compositions for use in diverse applications. Further, it is available in different hardness depending upon varying requirements of the customers.

3. The product under consideration is extensively used in cement build materials, metal mine, coal slurry, thermal power plant, chemical engineering, ceramic industry, dope industry, light industry such as papermaking and magnetic material etc for powder preparation. The subject goods are classified under Customs sub-heading 7325 9100 of Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

**Domestic Like Article**

4. The Applicants have claimed that there is no known significant difference in the subject goods produced by the Indian industry and the subject goods exported from the subject countries. The subject goods produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The

two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

5. Thus, the subject goods produced by the Applicants are being treated as like article to the product under consideration imported from the subject countries within the meaning of the AD Rules for the purpose of this investigation.

### Domestic industry & 'Standing'

6. The application has been filed by M/s AIA Engineering Ltd and M/s Welcast Steels Limited on behalf of the domestic industry. M/s Welcast Steels Limited is subsidiary of M/s AIA Engineering Ltd. As per the application, there are two more known producers of product concern in India.

7. As per information available on record, the Applicants account for over 90% of the total Indian production of the subject goods and thus the production of the Applicants account for a major proportion of the domestic production. It is evident from the above that the Applicants account for 'a major proportion' of total Indian production. The applicants therefore satisfy the 'Standing' requirement and constitute 'domestic industry' according to the AD Rules.

### Countries involved

8. The countries involved in the present investigation are China PR and Thailand (hereinafter also referred to as the subject countries).

### Normal value

#### China PR

9. The Applicants have claimed that China PR is a non market economy country. It has been further claimed that in the instant case Normal Value could not be determined by them on the basis of price or constructed value in a market economy third country as the relevant information is not publicly available and that the Normal value as described under the Statute is the "comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in such market economy third country". It has been claimed by them that they have not been able to procure such information from a producer in market economy third country. It has been further contended that price from market economy third countries to other countries could not be adopted as (a) the information is not available; (b) the price so adopted must be a price in the ordinary course of trade; (c) such information would also require co-operation from a producer in such third country. Also, prices from such third countries to India could not be adopted as the same might be influenced by the prices from the subject countries; and the product concerned involves a number of grades, which differs significantly in terms of associated cost as well as price. The Applicants have further claimed that India is an appropriate surrogate country for the producers in China PR.

10. In absence of sufficient information regarding the other methods as are enshrined in para 7 of Annexure I of the AD Rules, the Normal value has been determined by adopting the method "any other reasonable basis". Normal Value is thus has determined on the basis of

the cost of production of product concerned in India, including selling, general and administrative expenses and profit.

### Thailand

11. The Applicants have claimed that efforts were made by them to get evidence of prices of product concerned in the domestic market of Thailand and that efforts were also made to get any evidence of prices from published sources. However, despite making all reasonable efforts to procure authentic evidence with regard to actual transactions prices of sale of the subject goods in the domestic market of Thailand as well as the actual transaction prices at which the subject goods are being exported from Thailand to other countries, they could not procure adequate and accurate evidence in this regard. Therefore, they have determined Normal Value on the basis of estimated cost of production of GM Balls in Thailand.

12. However, the Authority collected the data in respect of exports of GM balls to third countries from Thailand. Although the data is not available on grade-wise basis, yet it has been considered as a *prima facie* evidence for determining the Normal value, on alternative basis, for the purposes of initiating this investigation.

### Export Price

13. The Applicants have determined export prices based on the data compiled by IBIS, Mumbai. The export prices have been adjusted for Ocean freight, Marine insurance, Commission, Inland transportation in the country of export, Port expenses, and Bank Charges etc to arrive at net export price at ex-factory level.

### Dumping margin

14. The applicants have provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, *prima-facie* indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

### 'Injury' and causal link

15. The Applicants have claimed material injury as a result of the alleged dumping of the subject goods from the subject countries. It has been claimed that the imports have increased in absolute terms and in relation to consumption in India and that the imports are significantly undercutting the prices of the domestic. The Applicant has further claimed deterioration in performance of the domestic industry in terms of market share, sales, Cash Profit, return on capital employed and inventories etc.

16. There is sufficient evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by the dumped imports from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation in terms of the AD Rules.

### Initiation of Anti Dumping Investigation

17. In view of the foregoing, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link

1855G1/11-3

between the dumping and 'injury' exists to justify initiation of an anti-dumping investigation.

“ Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent 'injury' to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping measure, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

### Period of investigation

18. The applicants have proposed October 2009 to September 2010 as period of investigation. While adopting this period as POI only for the purpose of initiation, the Authority has considered **January 2010 to December 2010 as the POI for the purpose of present investigation**. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2007-March 2008, April 2008-March 2009, April 2009-March 2010 and the Period of Investigation (POI) viz. January 2010 to December 2010. For threat of material injury, the data beyond the POI may also be examined.

### Submission of information

19. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
Room No.243, Udyog Bhawan,  
New Delhi -110107.**

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

### Time limit

21. Any information relating to this investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above mentioned address, not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

### Submission of information on Confidential basis.

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc. ) and (b) other set marked as Non-Confidential (with

title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

23. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

24. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary, a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Designated Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Designated Authority. The Designated Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

### Inspection of Public File

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

### Use of 'facts available'

29. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority